गुजरात में अन्तर्राष्ट्रीय विमान घर की आवश्यकता थी। विमान घर की हवाई पट्टी 9000 फीट लम्बी है। अन्तर्राष्ट्रीय विमानघर के लिए 12000 फीट लम्बी हवाई पट्टी चाहिए। इस वजह से सरकार ने 1991 अप्रैल में एक लाख बावन हजार फी–मीटर जमीन सम्पादित की थी। लेकिन सरकार ने इस जमीन में से 78 हजार फी–मीटर जमीन प्राईवेट मकान बनाने के लिए बेच डाली। अभी वहां सोसायटीज बन रही है।

अहमदाबाद शहर के विकास में जिसका अंतर्राष्ट्रीय महत्व बढ़ाने वाला है वहां अब अंतर्राष्ट्रीय विमानघर न बने ऐसा प्रयत्न राजकीय हित रखने वाले तत्वों ने किया है। गुजरात की जनता के साथ दगा किया है। अहमदाबाद का अंतर्राष्ट्रीय महत्व है। सरकार ने यह गंभीर गलती की है। अब फिर से विमान घर के लिए जमीन संचायित करना सरकार के लिए मुश्किल बन गया है। यदि फिर से जमीन संचायित करेगी तो गुजरात की जनता को करोड़ों रुपये देने पड़ेंगे। गुजरात की जनता सरकार को कभी माफ नहीं करेगी।

रनवे के लिए जमीन संचायित नहीं की गई तो अहमदाबाद में कभी भी अंतरारष्ट्रीय विमानघर नहीं बनेगा और विमानघर पर कभी भी जम्बो जेट जैसे विमान आ नहीं सकेंगे। प्रजा को इस सुविधा से वंचित रखने का किसी को अधिकार नहीं है।

मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहती हूं कि क्या यह बात आपकी जानकारी में है ? यदि है तो इसका ब्यौरा क्या होगा ? क्या जमीन फिर से संचायित करेंगे ? क्या अंतर्राष्ट्रीय विमानघर नहीं बनायेंगे ? अंतरराष्ट्रीय विमानघर कब बनेगा ? धन्यवाद।

श्री अनन्त राय देवशंकर दवे (गुजरात): मैं इससे अपने को एसोसियेट करता हूं और एक बात यह भी कहना चाहता हूं कि एयर पोर्ट अथारिटी ने जमीन ली थी और राज्य सरकार ने यह जमीन बेच डाली है या केन्द्रीय सरकार की जानकारी में यह है ? यदि है तो इस बारे में केन्द्र सरकार स्टेटमेंट दे। अगर रनवे के लिये जमीन नहीं ली गयी तो यहां कभी भी अंतराष्ट्रीय एयरपोर्ट नहीं बन सकता है।

Headless Public Sector Undertakings

डा० मुरली मनोहर जोशी (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो सार्वजनिक उपक्रमों से संबंध रखता है की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। महोदय लगभग 35 स्थान ऐसे हैं कि जिसमें सार्वजनिक उपक्रमों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नहीं हैं चीफ एक्जीक्यूटिव्स नहीं हैं। यहां तक कि जो उनको चयन करने वाला बोर्ड है पब्लिक इंटरप्राइजेज सलेक्शन बोर्ड, जो इस बात के लिये जिम्मेदार है कि वह सारे उपक्रमों के पदाधिकारियों को चयनित करें उसका भी कोई अध्यक्ष नहीं है, वह भी शीर्ष से खाली है। ये 35–36 संस्थायें बिल्कुल टापलेस आज पड़ी हुई हैं। इसका नतीजा यह है कि भारत के सारे उपक्रमों में भारी अव्यवस्था, भारी घाटा, भारी अनिश्चितता की स्थिति पैदा हो गयी है। नेशनल टैक्सटायल कारपोरेशन, राष्ट्रीय कैमिकल एंड फर्टिलाइजर, स्कूटर्स इंडिया, भारत भारी उद्योग निगम नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड, मंझगांव डाक, नेशनल हाईड्रो इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन, गैस अथारिटी आफ इंडिया, सेंट्रल इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, बंगाल केमिकल्स, भारत लेदर कारपोरेशन इत्यादि बहुत सारे उपक्रम ऐसे हैं जिनमें सी० एम० डी० नहीं है। आज इसका नतीजा यह हो गया है कि एच० एम० टी० जैसी कंपनी को सरकार कह रही है कि वह धीरे-धीरे अपने घाटे को पूरा करने

के लिये अपने लिये ज्वाइंट वेंचर करने वालों को ढूंढ ले। 1991-92 में यह संस्था बहुत अच्छी चल रही थी। उसमें किसी भी प्रकार का घाटा नहीं था, लेकिन धीरे-धीरे इसका घाटा बढ़ रहा है और अब यह कहा जा रहा है कि इसको पांच यूनिट्स में बांटकर इसको बेच दिया जाय। मैं अभी बंगलौर गया था। वहां के कर्मचारी मुझे मिले। उन्होंने आशंका व्यक्त की कि एच० एम० टी० जैसे कारखाने को जिसके बारे में स्वयं सरकार की रिपोर्ट है, जो इंडस्ट्री विभाग की रिपोर्ट है तो उस रिपोर्ट के अनैक्चर 4 में इसको 'गुड' काम करने वाली श्रेणी में रखा गया है। चार श्रेणियों में सारे उपक्रमों को बांटा गया है, एच० एम० टी० गुड श्रेणी में आती है लेकिन आज हालत यह हो गयी है कि आज एच० एम० टी० के कार्यकलाप भी संदेह के घेरे में आ गए हैं। वहां के लोगों में भारी आशंका पैदा हो गयी है।

मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या सार्वजनिक उपक्रमों के बारे में सरकार की कोई नीति है कि इनमें से किनको बेचा जायेगा, कब बेचा जायेगा और क्यों बेचा जायेगा ? क्या उनको लाभकारी बनाने के लिये सरकार की कोई नीति है ? अगर 35 इस प्रकार के कारखाने हैं जिनमें सी० एम० डी० नहीं है तो उनसे हम लाभ की आशा क्या कर सकते हैं ? दो हजार करोड़ रुपये से ऊपर देश के सारे उपक्रमों में लगे हुए हैं लेकिन वे 10 प्रतिशत या 5 प्रतिशत भी मुनाफा नहीं दे रहे हैं। ··· (व्यवधान) ·· प्रादेशिक सरकारों के भी हैं। सभी मिलाकर उद्योगों में इतना लगा हुआ है। सार्वजनिक उपक्रमों में, पब्लिक अंडरटेकिंग्स में और पब्लिक इंटरप्राइसेज में अगर आप देखें तो सरकार ने पिछले सालों ही में 33 हजार करोड़ रुपया सार्वजनिक उपक्रमों में इनवेस्ट किया है। अगर आप राज्य को भी देखेंगे तो मैं समझता हूं कि 2 लाख से भी ऊपर जायेगा जो कि कम नहीं है। आज इम्प्लाईमेंट घट रहा है। आज परिस्थिति यह है कि सरकार को इसके बारे में नीति का निर्धारण करना है या नहीं करना है ? वहां के कर्मचारियों के भविष्य के बारे में क्या विचार करना है? उनको लाभकारी कैसे बनाया जाय इसके बारे में क्या विचार करना है ?

मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि 35 कार्यकारी अधिकारियों को, सी० एम० डीज० को कब तक नियुक्त करेंगे और उसमें जो बाधाएं हैं उनको कैसे दूर करेंगे ? क्या सरकार की यह नीति है कि धीरे-धीरे इस तरह से इनको टॉपलेस छोड़ दो, बिक जांएं तो बिक जाएं भगवान के वास्ते। मेरा अनुरोध यह होगा कि बहुत महत्वपूर्ण मसला देश की अर्थ-व्यवस्था से संबंधित है, रोजगार से संबंधित है, कंपीटीटिवनेस से संबंधित है और नयी लिबरलाइजेशन एंड रीस्ट्रक्चरिंग से संबंधित है। आप इस पर स्पष्ट नीति निर्धारण करें। मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय यहां पर आएं और इस के बारे में सदन को आश्वस्त करें कि वह इस बड़ी भारी देश की अर्थ-व्यवस्था के बारे में, इनवेस्टमेंट के बारे में और प्रोडक्टीविटी के बारे में क्या निर्णय लेते हैं और किस तहर से इसको ठीक करेंगे। धन्यवाद।

SHRI MD. SALIM (West Bengal) : Sir, I associate myself with Dr. Joshi. Earlier also, when the same issue was raised in the form of question-answer and by way of Special Mentions, the Government promised that they would appoint CMDs in various public sector undertakings. What Dr. Joshi mentioned just now only goes to show the attitude of the Government in allowing the public sector undertakings to function without CMDs so that it would become easy for them to liquidate these public sector undertakings. Secondly, as Dr. Joshi also mentioned, these public sector undertakings have stopped recruiting staff under the guise of rationalisation or, what they call, proper utilisation of manpower. And they show,

in their Annual Reports, how well they have pruned the surplus staff. This would only make the youth of our country to go in search of overseas employment. In order to show themselves to be profitable, these companies have stopped recruiting people.

SRI B. K. HARIPRASAD (Karnataka): Sir, I would also like to associate myself with this Special Mention, especially, the aspect relating to HMT wherein about 26,000 workers are working all over the country. In Bangalore itself, around 15,000 people are employed in watch and machine tool industries. As the hon. Member has pointed out, over the last 40 years, this company has never suffered a loss except for a short period, namely, in the years 1967, 1968 and 1969, which was considered as a lean period. It is very unfortunate that there is a conspiracy hatched by, I would say, the top management for making the companies sick. It is a very unfortunate situation. The Government should come forward to the rescue of one of the major industries in Bangalore.

Thank you very much.

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI (Tamil Nadu) : Sir, what the hon. Member is saying is true. The Government should take a serious note of the situation.

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI Sir, HMT is one of the best units of our public sector undertakings. I am happy that Dr. Joshi has also expressed the view that our pulic sector undertakings should retain the glorifying heights... (*Interruptions*) Yes, they should retain the glorifying and commanding heights and they should earn profits by efficiency. But if there is no CMD heading a concern, who will give proper directions. So, I am in full agreement with him that these posts should be immediately filled so that proper directions can be given. I am sure that it is not the intention of the Government to liquidate the public sector undertakings. That impression, which is there in the mind of Doctor Saheb, should be completely discarded because all of us here and the Government also are fully committed to the efficient functioning of the public sector undertakings. There need not be any doubt in this regard. Otherwise, the Government would not have allotted this year more funds than the last year's Budget. So, I would request Dr. Joshi to discard his wrong impression. But if we want the public sector undertakings to function properly, then these vacancies should be filled immediately. Dr. MURLI MANOHAR JOSHI : I would request the hon. Member to impress upon the Government to get the CMDs and Chief Executives appointed and, thereby, allay the fears in the minds of the working class that they would be retrenched.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY) : The Minister will respond.

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE (West Bengal) : Sir, I fully associate myself with what Dr. Joshi said. As a matter of fact, the problem of sickness in the public sector undertakings has been due to lack of, what is called, succession planning. Whatever Dr. Joshi said is not happening only today but it is a matter of fact that in a major public sector undertaking, like the Hindustan Fertiliser Corporation, eight Chief Executives were changed over a span of 12 years. If the chief executive is not there, we can understand what type of corporate planning, what type of future planning can be done. This is my first point. My second point is... (*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY) : You cannot make a long speech. Now, Shri Muthu Mani.

NEED TO REVIEW THE ENTIRE LABOUR POLICY

SHRI S. MUTHU MANI (Tamil Nadu) : Mr. Vice-Chairman, Sir, I would like to bring to the notice of the Government the need to review the entire gamut of labour policy since the interests of the labour force have remained neglected over the years. Even the industrial relations have been showing a decreasing trend in the country.

The New Economic Policy of the Government has given room for several apprehensions in the labour force. The fear of large-scale retrenchment is still